>

Title: National Rural Employment Guarantee Scheme.

**कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर):** महोदय, आपने शून्यकाल में अतिआवश्यक लोकमहत्व के मामले को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नरेगा के तहत भारत सरकार साल में सौ दिन मजदूरों को काम देने की योजना को पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है। इसके लिए मजदूरों को जॉब कार्ड भी वितरण किए गए हैं। नरेगा शुरू होने से खेती के लिए किसानों को खेती के समय मजदूर मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इसमें से साठ रूपए किसानों को दिए जाएं और चालीस रूपए मजदूर को सीधे-सीधे मिले। उस साठ रूपए से किसान सिंचाई हेतु बिजली का बिल भी अदा करेगा और अपनी तरफ से और पैसा मिलाकर मजदूरों का भुगतान भी करेगा। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। इसके लिए सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार को पेट्रोल से प्रति लीटर एक रूपया और डीजल से पचास पैसे राजस्व मिलता है। इस तरह मजदूरों को साल के 365 दिन काम मिलता रहेगा और सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु मजदूर भी समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। मजदूरों को अपने गृह स्थान पर 365 दिन काम मिलने लगेगा। महंगाई भी कम होगी और किसान समय पर खेती करा सकेगा। किसानों की आत्महत्या रूकेगी और हर कृषि क्षेत्र का समान रूप से विकास होगा तथा राष्ट्र भी आत्म निर्भर होगा।

अतः केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि यह विषय काफी गंभीर है और इस मामले को सरकार संज्ञान में लेकर नरेगा में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करे।